परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं।
– अज्ञात

समाप्त करे या और आगे बढ़ाए!

इस सप्ताह के आखिर तक सभी राज्य इस आशय वाली अपनी–अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे और उसके आधार पर केंद्र सरकार फैसला करेगी। अभी जैसा लग रहा है, पूरे देश से एक साथ लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाएगा।

राधा जोशी।

21 दिनों का लॉकडाउन ज्यों–ज्यों अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, सरकार की दुविधा भी बढ़ रही है कि वह इसे पूरी तरह समाप्त करे या और आगे बढ़ाए। अभी स्थिति यह है हर दिन के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या में पांच सौ या इससे ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, जिससे अंदर ही अंदर एक ऐसे संकट को मजबूती मिल रही है, जो आगे चलकर विस्फोटक रूप ले सकता है। इनके अलावा तीसरा फैक्टर यह है कि खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लॉकडाउन को कोरोना से लड़ने का पर्याप्त उपाय नहीं माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस मसले पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें तय हुआ कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन हटाने का प्लान भेजा जाए। इस सप्ताह के आखिर तक सभी राज्य इस आशय वाली अपनी–अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे और उसके आधार पर केंद्र सरकार फैसला करेगी। अभी जैसा लग रहा है, पूरे देश से एक साथ लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार की योजना है कि जिन जगहों पर कोरोना के केस ज्यादा पाए गए हैं वहां लॉकडाउन जारी रखा जाए।

संक्रमण की मात्रा के आधार पर राज्यों को चार कैटिगरी में बांटा जाएगा और उसी हिसाब से अलग–अलग राज्यों या फिर जिलों में लॉकडाउन हटाने और विभिन्न सेवाएं शुरू करने के बारे में सोचा जाएगा। इनमें ज्यादा एक्टिव कोरोना वाले इलाकों में लॉकडाउन से कोई छूट नहीं दी जाएगी लेकिन जिन राज्यों में पिछले सात दिन से कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो, वहां राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि 24 मार्च की आधी रात से पूरे देश में तीन हफ्ते के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यों–ज्यों लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, समाज के कमजोर वर्ग की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी।

अभी यह तबका किसी तरह जीवन यापन कर रहा है लेकिन वह कब तक इस तरह बैठा रहेगा? असंगठित और छोटे स्तर के धंधे पूरी तरह चौपट हो गए हैं। निर्माण कार्यों का चक्का एकदम रुका हुआ है। छोटे–मोटे खाने–पीने की दुकानें और तमाम तरह की सर्विसेज बंद हैं। फैक्ट्रियों के बंद होने से चिकित्सकीय सामग्री भी नहीं बन पा रही है। ऐसे में रास्ता यही बचता है कि चुनिंदा दायरों मे उत्पादन कार्य किसी तरह शुरू हो ताकि हम चिकित्सा उपकरण और खाद्य सामग्री बना सकें। इससे खाली बैठे श्रमिकों को काम मिलेगा, चिकित्साकर्मियों को जरूरी उपकरण मिल सकेंगे और लोगों की जांच का काम भी तेज होगा। लेकिन लॉकडाउन में जरा भी ढील सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर समस्या पैदा कर सकती है, लिहाजा इसके लिए भी कोई रास्ता खोजना होगा। सरकार सभी पहलुओं पर सोच–विचार करके ही कोई फैसला करेगी।

हार नहीं मानते

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

मगर सपने इतनी आसानी से हार नहीं मानते। दिल की अतल गहराइयों में छुपा कर रखें तो भी वे उन लोगों से छुपे नहीं रहते, जो आपके दिल में रहते हैं। यह बात साफ हुई उनके जाने के काफी समय बाद, जब इन्हीं सपनों का पीछा करते हुए उम्र के नौवें दशक में चल रहीं उनकी पत्नी पिछले दिनों अकेली गांव जाकर बैठ गईं, पैतृक घर और गांव का हनुमान मंदिर बनवाने। बेटे–बेटियों से लेकर मित्र–रिश्तेदारों की तमाम अगर–मगर एक तरफ और उनका संकल्प एक तरफ। स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याएं और कोरोना वायरस से जुड़े सभी खतरे एक तरफ और उनका यह संकल्प एक तरफ कि जिंदगी रहेगी तो यह काम होकर रहेगा। भले ही यह आज पूरा हो या जनता कर्फ्यू और कंप्लीट लॉकडाउन जैसी बाधाएं पार कर लेने के बाद।

संपादकीय

डोनेशन पर सवाल

इस बीच कोरोना और आर्थिक संकट के मद्देनजर विदेशों से डोनेशन लेने के मुद्दे पर भी सवाल उठ गए हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र सकार पर आरोप लगाया कि वह इसके लिए पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए विदेश से मदद मांग रही है। ऐसा तब हुआ जब इसके लिए गठित पीएम केयर्स फंड में विदेशों में बसे भारतीयों से भी डोनेशन स्वीकार किए जाने का प्रावधान किया गया। विपक्षी दलों का कहना है कि यह खुद सरकार के बनाए मानक के खिलाफ है।

दरअसल 2019 में यूएई ने केरल बाढ़ की मदद के लिए 700 करोड़ की मदद देने का एलान किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने तब इसे लेने से मना कर दिया था। उसने दलील दी थी कि भारत विदेशी डोनेशन नहीं लेता है। उसी फैसले को दिखाते हुए विपक्ष इस बार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इन दो सालों में क्या फर्क आ गया। इससे पहले 2004 में सुनामी के बाद भी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंहने विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया था।

2013 में उत्तराखंड त्रासदी के दौरान भी भारत ने रूस से मदद लेने से इनकार किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बेवजह का मुद्दा बताया है। उसका कहना कि सरकार के स्टैंड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। पीएम केयर्स फंड में विदेशों से डोनेशन लेने को लेकर बहुत सारी गलत बातें कही जा रही हैं। वास्तवमें पीएम केयर्स फंड के गठन के समय इतना ही कहा गया था कि इसमें विदेशों में बसे भारतीयों और उनके संगठनों से मदद ली जाएगी। यह प्रावधान प्रधानमंत्री नैशनल रिलीफ फंड में डोनेशन के लिए बने मानकों के अनुरूप ही है। 2011 से ही इसमें ऐसे संगठनों से मदद ली जाती रही है।

आम लोग खासकर गरीब जनता पर कम से कम बोझ डालेगी उससे जुड़े दल को भविष्य में इसका अधिक से अधिक राजनतिक लाभ मिलना तय है।

राज्यों का गुणा-भाग

नरेंद्र नाथ ।

कोरोना संकट का मुकाबला करते हुए भारत मुंह खोले खड़े आर्थिक संकट से जूझने के लिए भी खुद को तैयार करने लगा है। माना जा रहा है कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना पूरा विश्व कर रहा है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि न्यूनतम आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ से अधिक रकम की तत्काल जरूरत पड़ेगी। ये फंड कहां से आएगा, इसे खर्च कौन करेगा, किस तरह से करेगा और किन राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा– जैसे सवालों पर भी हिसाब–किताब शुरू हो गया है। तमाम राज्य अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर राहत पैकेज में अधिक से अधिक हिस्सा पाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने लगे हैं।

दरअसल केंद्र ही नहीं तमाम राज्य सरकारों को भी आभास है कि कोरोना संकट से निकलने के बाद जो राज्य सरकार आर्थिक मोर्चे पर बेहतर काम करेगी और आम लोग खासकर गरीब जनता पर कम से कम बोझ डालेगी उससे जुड़े दल को भविष्य में इसका अधिक से अधिक राजनतिक लाभ मिलना तय है। अगर राजनीतिक नफा–नुकसान से हट कर भी देखें

तो सभी राज्य सरकारें संकट के समय में अपने लोगों के साथ सबसे मजबूती से खड़ी दिखना चाहेंगी। कोरोना बीमारी का प्रभाव भले सभी राज्यों पर समान रूप से नहीं पड़ता दिख रहा हो लेकिन आर्थिक रूप से सभी राज्य एक समान प्रभावित होंगे।

11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉक डाउन की आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करी। इस बार खासकर विपक्षी राज्यों के सीएम ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वे राज्यों को अधिक से अधिक आर्थिक राहत देने की मांग उठाएंगे। छत्तीसगढ़,पंजाब और राजस्थान जैसे कांग्रेस प्रभावित राज्य पहले ही केंद्र से तत्काल राहत पैकेज देने की मांग कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी इस दिशा में केंद्र से आग्रह कर चुके हैं। महाराष्ट्र की सरकार भी केंद्र से अतिरिक्त फंड इस मीटिंग में मांग सकती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों ने तो कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी किश्तों में देने का निर्णय लिया।

बुधवार को भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की थी तो उसमें यह मुद्दा उठा था। बिहार के जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मीटिंग में बिहार सहित सभी राज्यों को आर्थिक मदद दिए जाने की बात उठाई। जेडीयू बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। मीटिंग में पीएम मोदी ने उनकी बात को पूरा सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा कई राज्यों ने सांसद निधि की राशि को दो साल के लिए स्थगित कर उसकी राशि पीएम केयर्स फंड में दिए जाने पर भी सवाल उठाए। खासकर विपक्षी राज्यों ने सवाल किया कि इस फंड से सांसद अपने क्षेत्र में कोरोना प्रभावित लोगों के बीच ही मदद कर सकते थे लेकिन अब उनके पास इसका कोई संसाधन नहीं है।

इसी बीच बिहार सहित कई राज्यों ने केंद्र को बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा कि सांसद निधि से जमा राशि को राज्यों से मिले हिस्से के अनुरूप बांट दे और राज्य सरकार अपने यहां संबंधित सांसदों से कोरोना राहत में खर्च कराए। बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को ओडिशा जैसे राज्यों का भी सपोर्ट मिला।

सूडोकु नवताल-5316

सरल

5	9			3			8	7
8	7		1		5			
		2			9			4
	6				2		3	5
3	8		4	1	7		2	9
2	4		6				1	
7			3			8		
			5		8		7	3
9	3			2			6	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5315 का हल

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

7	4	8	3	9	2	1	5	6
2	6	9	5	7	1	8	4	3
3	1	5	4	8	6	7	2	9
5	7	4	8	6	9	3	1	2
8	9	1	2	3	4	6	7	5
6	3	2	1	5	7	4	9	8
4	8	7	6	2	5	9	3	1
9	2	6	7	1	3	5	8	4
1	5	3	9	4	8	2	6	7

अपना ब्लॉग

निर्भर गरीब मजदूर की व्यवस्था हो

मोहन। सरकार को निजी कंपनियों एवं छोटे व्यवसायों की कैंटीनों को खोलने की कवायद करनी चाहिए, ताकि बाहरी खाने पर निर्भर गरीब मजदूर की व्यवस्था हो और वह उसी के आसपास रहकर लॉकडाउन काटे। महाराष्ट्र जैसे राज्य में 19 मार्च को सरकारी राशन देने के लिए अध्यादेश तो जारी हुआ, लेकिन अब तक किसी भी नागरिक को राशन नहीं मिला है। सरकार को लोगों को दुकानों पर बुलाने के बजाय एनजीओ, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और पुलिस की मदद से घरों तक राशन, दवाईयां और अन्य चीजों को पहुंचाने के लिए पहल करनी चाहिए, ताकि लोग खाद्य सामग्री के नाम पर घर के बाहर न आएं। सरकार को बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन के लिए बिस्तरों की उपलब्धता पर भी जोर देना चाहिए। डॉक्टरों और नर्सों को भी सुरक्षा कवच पहनाने की अत्यधिक आवश्यकता है, ताकि वे कोरोना से बचे रह सकें। इसके अलावा सरकार को हर हाल में होम डिलेवरी चेन एक्टिव करनी ही होगी, ताकि लोग घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें।